जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 31 संख्याः 232 प्रभात उदयपुर, मंगलवार 25 जून, 2024 आर.जे. 7202 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

एन.डी.ए. के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी हुईं संसद में

ओडीशा के पूर्व मु.मंत्री नवीन पटनायक ने राज्यसभा में अपने नौ सांसदों को हिदायत दी कि, राज्यसभा में सजीव व सशक्त विपक्ष की भूमिका निभायें, एन.डी.ए. को समर्थन देने की बिल्कुल न सोचें

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले सत्तारुढ़ एन.डी.ए. के सामने चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं, ओडीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि, राज्य सभा में अपने नौ सांसदों के साथ बीजू जनता दल (बी.जे.डी.) भाजपा को समर्थन नहीं देगा।

नवीन पटनायक ने अपने सांसदों से यह भी कहा है कि, वो अपने राज्य के हितों से संबंधित मुद्दों को उपयुक्त तरीके से जोर-शोर से उठाएं। बी.जे.डी. सुप्रीमो ने अपनी पार्टी के नौ राज्यसभा सांसदों से कहा है कि, संसद के उच्च सदन में वो "सजीव व सशक्त" नेता बनकर उभरें।

सोमवार को पटनायक की सांसदों के साथ हुई बैठक में यह संदेश दिया गया।

- अब तक बी.जे.डी., एन.डी.ए. को महत्वपूर्ण मुद्दों पर समर्थन करती आई थी। पर, बी.जे.डी. की नई लाइन होगी, ओडीशा का हित सर्वोपरि रहेगा, तथा अगर मोदी सरकार, ओडीशा के हितों की अवहेलना करती है तो बी.जे.डी. के सांसद (राज्यसभा सदस्य) जमकर विरोध करेंगे।
- बी.जे.डी. (बीजू जनता दल) ने ओडीशा की, कोयले की रॉयल्टी बढ़ाने की पुरानी मांग व ओडीशा में मोबाइल कनेक्टिविटी कमज़ोर होने तथा नैशनलाइज्ड बैंकों की बहुत कम शाखाएँ होने की पुरानी शिकायतों को दोहराया।
- अब तक बी.जे.डी. "इशू बेस्ड" समर्थन ही नहीं देती थी, एन.डी.ए. को, बल्कि अन्य मौकों पर एन.डी.ए. की ओर सहायता का हाथ भी बढ़ाती थी, जैसे, 2019 से अब तक रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को, ओडीशा का राज्यसभा सदस्य बनाकर भेजने में पूर्ण मदद की थी।
- दूसरी और प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तीन पेज का खत लिखकर प्र.मंत्री मोदी को शिकायत दर्ज कराई है कि, हाल ही में बांग्लादेश की प्र.मंत्री से गंगा व तीस्ता नदी तथा, फरक्का बैराज से पानी के बंटवारे पर बातचीत की, तथा प.बंगाल को इस बातचीत में शामिल नहीं किया, यह अनुचित है। क्योंकि बंगाल व बांग्लादेश के भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध हैं, जिसकी गहराई शायद कोई और नहीं समझ सकता है।

बी.जे.डी. के राज्यसभा सांसद, सस्मित पात्रा ने पत्रकारों से कहा, "इस बार बी.जे.डी. सांसद केवल मुद्दों पर बोलने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि, आंदोलन करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, यदि केन्द्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने ओडीशा के हितों की अनदेखी की।"

ओडीशा के लिए विशेष दर्जे की मांग उठाने के अलावा, बी.जे.डी. के सांसद, राज्य में मोबाइल की खराब कनैक्टिविटी और राज्य में नैश्नलाइज़्ड

(शेष पृष्ठ 5 पर)

इमर्जेंसी के खिलाफ आज भाजपा का विरोध प्रदर्शन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। भारतीय जनता पार्टी को सोमवार को अचानक "लोकतंत्र के काले दिनों की याद में देशव्यापी स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की याद आई, ज्ञातव्य है कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था।

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया अध्यक्ष

- 49 साल पहले सन् 1975 में 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। भाजपा के इस कदम को कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन में अलग-थलग करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

अनिल बलूनी ने उन दिनों को याद कर कहा कि किस प्रकार आपातकाल लागू होने के अगले 21 महीनों तक कांग्रेस सरकार ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बंधक बना लिया था तथा जनता, मीडिया व विपक्षी नेताओं पर बेशुमार अत्याचार किए गए थे। भाजपा का यह विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के संविधान बचाओ कार्यक्रम का जवाब है। उसका यह कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी नहीं

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ममता बनर्जी ने केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन भेजा नीट परीक्षा पर

"नीट परीक्षा प्रणाली रद्द हो, तथा राज्य सरकार द्वारा मैडिकल कॉलेजों मे प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने का अधिकार राज्य सरकारों को पुनः दे दिया जाये, जैसा कि, 2017 से पहले था"

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सरकारी नौकरियों की परीक्षा में हेरा-फेरी कर भारी घोटाला करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मैडिकल प्रवेश की परीक्षाएं राज्यों में ही आयोजित करने वाले पुराने सिस्टम को बहाल करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को एक प्रतिवेदन भेजा है।

उन्होंने शहरी क्षेत्रों में विफल रहने वाले तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ ही निगम में अपने स्वयं के निर्वाचित अधिकारियों की जोरदार खिंचाई शुरू कर दी है। उन्होंने वह काम शुरू कर दिया है, जिसमें वे माहिर हैं, यानी कि नए से नए आंदोलन शुरू करना, ना कि सुशासन पर ध्यान देना।

- ममता बनर्जी का तर्क है कि, सन् 2017 से पहले इतना व्यापक भ्रष्टाचार नहीं था, एडमिशन की परीक्षाओं में जितना अब है।
- ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि, हर डॉक्टर को तैयार करने में राज्य सरकार लाखों रूपए खर्च करती है, अतः उनके चयन में भी राज्य सरकार की दखल होनी चाहिये।
- पर, यह भी सच है कि, ममता बनर्जी को यह ज्ञान अब प्राप्त हुआ, जब उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले झटका लगा, शहरी क्षेत्रों में, म्युनिसिपल एरियाज़ में।
- नयी ममता ने यह स्वीकारते हुए अपने प्रशासन व वरिष्ठ नेताओं की भी भर्त्सना की, जिन्होंने शहरी क्षेत्रों में अपने कृत्यों से बदइंतजामी व भ्रष्टाचार फैलाया था।

यह सर्वविदित है कि राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया तृणमूल के उन नेताओं द्वारा दूषित कर दी गई जिन्होंने नौकरी के इच्छुक लोगों से भर्ती प्रक्रिया के लिए रिश्वत ली थी। सी.बी.आई. ने सरकारी नौकरियों के घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कुछ शीर्ष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के दौरान यह पता चला कि सरकारी भर्ती में तृणमूल की संलिप्तता रही है।

इसके विपरीत ममता ने अब नीट व नैट परीक्षाओं में पेपर लीक पर हमला बोला है। उन्होंने इस घोटाले के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेवार माना है। ममता बनर्जी का मानना है कि पहले के सिस्टम में राज्य मेडिकल एन्ट्रैन्स परीक्षा आयोजित करते थे, जिसमें

(शेष पृष्ठ 5 पर)

कांग्रेस सांसदों ने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली

प्र.मंत्री मोदी द्वारा लोकसभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस ने संविधान की प्रति लहराई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून, लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को जैसे ही सदस्यता की शपथ ग्रहण की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य पार्टियों के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की प्रति दिखाई, क्योंकि प्रो-टैम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ सांसद भी हैं, ने सबसे पहले मोदी को सदस्यता की शपथ दिलाई थी। और उसके बाद सांसदों को। कांग्रेस के बहुत सारे सांसदों ने उनके हाथों में संवधािन की प्रति पकड़े हुए शपथ ग्रहण की।

- शुक्रवार को नई लोकसभा की शुरुआत हुई। पहले दिन प्रो-टैम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने नए सांसदों को शपथ दिलाई।
- पहले दिन लोकसभा 6 बजे स्थगित हो गई, अतः मंगलवार को भी शपथ ग्रहण जारी रहेगा।

सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा क्योंकि सदन सोमवार को शाम 6:00 बजे स्थगित हो गया। महताब के कामकाज में भाजपा के दो सांसदों ने सहयोग किया, क्योंकि कांग्रेस के सांसद के. सुरेश कुमार ने वरिष्ठतम सांसद होने के बावजूद राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उन्हें प्रो-टैम स्पीकर नियुक्त नहीं करने के विरोध में विपक्ष ने राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गठित पैनल में नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया। इस विरोध के जवाब में सरकार का जवाबी तर्क यह है कि महताब, जो बीजू जनता दल (बी.जे.डी.) से दल बदलकर आये थे उनकी आठवें कार्यकाल तक निरन्तरता रही है जबकि सुरेश के कार्यकाल में ब्रैक था।

पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को यह स्वीकार्य नहीं है कि प्रधानमंत्री व गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला करें और यही कारण है कि पार्टी के सांसद शपथ ग्रहण करते समय संविधान की प्रति अपने हाथ में लिए हुए हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे सही संदेश जाता है। इस पर राहुल ने कहा कि संदेश जोरदार व स्पष्ट है कि संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके या उसे नष्ट कर सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही सरकार को बचाने के लिए बैकफुट पर हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत इंडिया गठबंधन अपना दबाव बढ़ाएगा और लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करेगा ताकि प्रधानमंत्री मोदी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अधिकतम 10 टन गेहूँ का स्टॉक रखा जा सकता है

नई दिल्ली, 24 जून (वार्ता)। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए पूरे देश में गेहूं के स्टॉक पर तत्काल प्रभाव से उच्चतम सीमा लागू कर दी है। यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।

मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के

- सरकार ने गेहूं के स्टॉक पर तत्काल प्रभाव से उच्चतम सीमा लागू कर दी है। यह आदेश 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। अधिकतम 10 टन गेहूँ का भंडारण किया जा सकेगा।

अनुसार, समठा खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी और बेईमानी से की जा रही सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाने का निर्णय लिया है।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

भाजपा ने तमिलनाडू शराब दुखांतिका पर कांग्रेस के मौन पर सवाल उठाए

भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख कर कहा, आदिवासियों की मौत पर कांग्रेस की चुप्पी पर मैं स्तब्ध हूँ

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। कोलकाता ट्रेन दुर्घटना और नीट पेपर लीक पर देशभर में हो रहे प्रदर्शनों के कारण विपक्ष के दबाव में आई भाजपा को भी इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है भाजपा ने तमिलनाडु में हुई अवैध शराब दुखांतिका को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। इस हादसे में 58 लोग मारे जा चुके हैं तथा कई अस्पताल में भर्ती हैं।

भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक कड़ा पत्र लिखा और "मैन मेड" विनाश पर चुप्पी के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारण हुई ये मौते टाली जा सकती थीं उन्होंने इस घटना की सी.बी.आई. से जांच कराने की मांग की।

- नड्डा ने कहा कि, तमिलनाडू का गांव करूणपुरम, जहाँ ज़हरीली शराब पीने से 58 लोग मरे हैं, वह अनुसूचित जाति बहुल गांव है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से कहा, अनुसूचित जाति के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए।
- नड्डा ने कहा, अब समय है "न्याय" की बात करने का। आप "न्याय" को एक असफल नेता को स्थापित करने की कोशिश में मात्र एक आकर्षक "नारे" की तरह ही इस्तेमाल ना करें।
- कोलकाता ट्रेन हादसे, नीट पेपर लीक, जैसे मुद्दों पर बुरी तरह से विपक्षी इंडियाा गठबंधन के निशाने पर आई भाजपा सरकार को तमिलनाडू हादसे ने विपक्ष पर पलवार करने का हथियार दे दिया है।
- नड्डा ने कहा कि, इंडिया गठबंधन के दलों में अवैध शराब का धंधा करने व शराब घोटाला करने की प्रवृत्ति निहित है।

नड्डा ने अपने पत्र में लिखा, जब इतना बड़ा हादसा हुआ तब मैं स्तब्ध रह गया। आपके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने इस पर चुप्पी साधे रखी है। इस समय भाजपा और पूरा देश आपसे मांग करता है कि आप द्रमुक, जो तमिलनाडू में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करता है से इस हादसे की सी.बी.आई.जांच से करवाने तथा मुथुस्वामी को मंत्री पद से हटाने के लिए कहें।

तमिलनाडु में भाजपा सहित सभी विपक्षी दलो ने पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया है और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से इस्तीफा मांग रहे है। नड्डा ने कहा कि अगर द्रमुक सरकार व अवैध शराब माफिया की सांठ-गांठ नहीं होती तो ये जाने बच सकती थी।" भाजपा प्रमुख ने कहा कि, अवैध शराब दुखांतिका के बाद करुणापुरम गांवों में इतनी सारी चिताए जलने का दृश्य बेहद डराने वाला है। इस हादसे में 159 लोग अस्पताल में भर्ती है। इस घटना ने देश के जनमानस को झरझोर दिया है।

भाजपा प्रमुख ने कांग्रेस अध्यक्ष को कहा कि करुणापुरम गांव, जहां यह हादसा हुआ है, में अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है जिन्हें तमिलनाडु में भारी भेदभाव और गरीबी सहनी पड़ती

(शेष पृष्ठ 5 पर)

इंडिया और एन.डी.ए. के बीच राउण्ड-2 मुकाबला

नई दिल्ली, 24 जून। लोकसभा चुनाव के बाद अब देश में 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाला एन.डी.ए. और विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन इसे लेकर तैयारियों में जुट गया है। मालूम हो कि आम चुनाव में भाजपा

- 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग होगी। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे।

बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई जबकि इंडिया ने अपनी संख्या और ताकत काफी मजबूत कर ली। 7 राज्यों की 13 विधानसभा क्षेत्रों में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। राजस्थान में पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये सीटें विभिन्न दलों के मौजूदा विधायकों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। इनमें बिहार की रूपौली, पश्चिम बंगाल

(शेष पृष्ठ 5 पर)

संसद के पहले ही दिन प्र.मंत्री मोदी व इंडिया गठबंधन के नेता खड़गे के बीच झड़प देखने को मिली

झड़प का मुख्य मुद्दा रहा, "एमरजैंसी शब्द" की परिभाषा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जून। लोकसभा चुनावों के बाद संसद के प्रथम सत्र में ही आज सत्तारूढ़ एन.डी.ए. और इंडिया गठबंधन के बीच झड़प हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच "आपातकाल" शब्द को लेकर वाक्युद्ध छिड़ गया।

मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। आज सुबह लोकसभा की बैठक शुरु होने से पूर्व प्रधानमंत्री ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को निशाना बनाते हुए "आपातकाल" को लेकर प्रहार किया।

प्रधानमंत्री ने सदन की बैठक शुरु होने से पूर्व मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कल 25 जून आपातकाल की 50वीं बरसी होगी। उन्होंने इसे देश के लोकतंत्र पर एक "काले धब्बे" की संज्ञा दी।

- प्र.मंत्री मोदी ने कहा, 25 जून, इंदिरा गांधी द्वारा घोषित "एमरजैंसी" को पचास साल पूरे होंगे तथा भारत की जनता इसे हमारे प्रजातंत्र को सबसे काले धब्बे के रूप में याद करेगी, जब संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई थीं, देश को विशाल जेल में परिवर्तित हो गया था।
- खड़गे ने प्रत्युत्तर में कहा कि, प्र.मंत्री को पचास साल पुरानी "एमरजैंसी" तो याद है, पर, वो एमरजैंसी याद नहीं, जो गत दस साल से भाजपा ने देश पर लाद रखी है। जनता को वर्तमान "एमरजैंसी" कतई स्वीकार नहीं, और जनता ने अपनी राय लोकसभा चुनाव में साफ जाहिर कर दी है, स्टाम्प लगाकर, भाजपा को बहुमत प्रदान न करके।
- प्र.मंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कहा कि, साठ साल बाद यह मौका आया है कि, जनता ने तीसरी बार लगातार किसी सरकार को जिता कर भेजा है। आशा है विपक्ष इस निर्णय की गरिमा को स्वीकार करेगा, क्योंकि जनता जिम्मेवार विपक्ष चाहती है, तथा संसद में बहस, मंथन चाहती है, न कि, शोर शराबा व लगातार व्यवधान।
- पहले दिन के घटनाक्रम से यह तो साबित हुआ कि, यह तो स्वीकार कर लिया गया है कि, भाजपा को झटका लगा है, पर, प्र.मंत्री मोदी सदन को विपक्ष की मनमर्जी अनुसार हांकने नहीं देंगे, तथा किसी विपक्षी दल नेता को वो महत्व व स्थान नहीं देना चाहते, जो विपक्ष समझता है कि, वह उसका हकदार है।

कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि "आप विपक्ष को चेतावनी दे रहे हैं। आप 50 साल पुराने आपातकाल की बात कर रहे है, लेकिन आप पिछले 10 सालों से चल रहे अघोषित आपातकाल को भूल गए हैं।"

खड़गे ने कहा कि देश की जनता ने मोदी जी के खिलाफ जनादेश दिया है तथा इंडिया गठबंधन संसद के भीतर और बाहर जनता की आवाज़ उठाएगा।

संसद का वर्तमान सत्र देश में आम चुनाव सम्पन्न होने के बाद आयोजित किया जा रहा हैं और विपक्ष लोकसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित है, जिसमें उसने भाजपा को बहुमत का आंकड़ा छूने से रोक दिया था। ऐसा लगा कि एन.डी.ए. सहयोगियों के समर्थन से पुनः प्रधानमंत्री पद पर लौटे प्रधानमंत्री विपक्ष को उचित सम्मान देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं और टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार थे। विपक्ष की योजना अपने संख्याबल के बलबूते पर सरकार को सदन में घेरने की है। तथापि, प्रधानमंत्री के भाषण शैली से समझ में आता है कि भाजपा को लोकसभा चुनावों में भले ही आघात लगा हो, किन्तु विपक्ष को अपनी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

"ब्रिटानिया" की 70 साल पुरानी फैक्टरी बंद

कोलकाता, 24 मई। कोलकाता में "ब्रिटानिया" की 70 साल से चल रही फैक्टरी बंद हो गई है। फैक्टरी के बंद होने को लेकर भाजपा ने टी.एम.सी. की सरकार पर हमला बोला है।

- भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि, कोलकाता की इस फैक्टरी का बंद होना वास्तव में बंगाल के पतन का प्रतीक है। एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था, वह आज पतन के रास्ते पर है।

ब्रिटानिया ने घोषणा की है कि उसके फैक्टरी के सभी कर्मचारियों को वी.आर.एस. पर भेजा जा रहा है और

(शेष पृष्ठ 5 पर)